# इकाई 10 जापान में आधुनिकीकरण-I

### इकाई की सपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 शाही सरकार की स्थापना
10.2.1 विशेषाधिकारों की समाप्ति
10.2.2 राष्ट्रीय सेना
10.2.3 भूमि-कर और पेंशन

10.3 संविधान की ओर 10.3.1 मेजी का संविधान

10.3.2 बहस

10.4 मेजी राज्य के विरुद्ध विरोध और विद्रोह 10.4.1 विशेषाधिकारों की समाप्ति के विरुद्ध 10.4.2 स्वतंत्रता और जनाधिकार आंदोलन

10.5 मेजी की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति10.5.1 सम्राट10.5.2 नौकरशाही

10.6 सारांश

10.7 शब्दावली

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

### 10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बादः

- आपको मेजी नेतृत्व द्वारा एक संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी होगी.
- आप एक संवैधानिक प्रतिनिधि सरकार की विपक्ष की मांगों के बारे में जानेंगे, और
- आप मेजी राज्य की प्रकृति और सम्राट व्यवस्था के अर्थ को समझ सकेंगे।

#### 10.1 प्रस्तावना

जैसा कि हम पहले ही इकाई 9 में बता चुके हैं, जनवरी, 1868 में अंतिम शोगुन (गवर्नर) तोकुगावा केके ने सम्राट के पक्ष में अपना पद त्याग दिया था। सिद्धांत रूप में शोगुन ही सम्राट के नाम पर राज्य करते आए थे, लेकिन व्यवहार रूप में शोगुन ही असली शासक थे जबिक सम्राट क्योटो में रहने वाला और आर्थिक रूप से शोगुन पर आश्रित एक विस्मृत या उपेक्षित व्यक्ति था। यह शांतिपूर्ण कदम एक लंबी और जिटल प्रक्रिया की परिणित थी जिसके जिरए ढाई सौ वर्ष जापान पर राज्य करने वाली तोकुगावा गवर्नरी का अंत हो गया।

मेजी पुर्नस्थापना का नेतृत्व सत्सुमा और चोशू के **हान** ने किया था, जिसके नेताओं ने नयी सरकार पर अपना प्रभुत्व बनाया। मेजी अल्पतंत्र भी कहलाने वाले इस शासन ने व्यापक सुधारों की शुरुआत की ओर एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के संस्थायी ढांचे को खड़ा किया। उन्हें विश्वास था कि पश्चिमी ताकतों को यह स्वीकार्य होगा। ये बदलाव तेजी से लाये गये और चालीस वर्षों के अंदर ही जापान दुनिया की एक ऐसी ताकत के रूप में उभर चुका था जिसके पास एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक सशक्त सैनिक क्षमता थी। इस इकाई में, इस नये बने राजनीतिक ढांचे की प्रकृति, विशेषता और प्रक्रिया की छानबीन की जाएगी। यहां जिन राजनीतिक सुधारों की चर्चा की गयी है उनमें से कुछ पर खंड 4, इकाई 16 में भी विचार किया गया है, लेकिन यहाँ हम उन सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने मेजी अल्पतंत्र और विपक्ष को भी प्रेरित किया।

### 10.2 शाही सरकार की स्थापना

मेजी सरकार ने पुराने शासन के ढांचे को गिराने के लिए तुरंत कदम उठाए । 3 जनवरी, 1869 को ही पुराने विभागों को समाप्त करके एक शाही युवराज के नेतृत्व में एक नयी परिषद का गठन कर लिया गया। ये बदलाव अंतिम नहीं थे और नये शासकों की शक्ति का विस्तार होने और उनका नियंत्रण बढ़ने के साथ ही कई नये बदलाव लाये गये। नये शासकों ने कुछ बड़े कदम उठाकर कुछ बाधाओं को पार किया।

### 10.2.1 विशेषाधिकारों की समाप्ति

सत्ता के नए आधार को मजबूत करने की दिशा में सबसे पहली बड़ी बाधा थी **वाइम्यों** और **सैमुराई** को प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त करना। **वाइम्यों** को कुछ हद तक स्वायत्तता भी प्राप्त थी। **वाइम्यों** के विशेषाधिकारों की समाप्ति को एक पुराने किस्म के सामंती ढांचे को गिराने और सम्राट की सत्ता की पुष्टि के रूप में देखा गया। विरोध के भय से नेता कुछ हिचकिचाये, लेकिन पहला कदम तब उठा जब **वाइम्यों** को यह आदेश जारी किया गया कि वे ''सार्वजनिक'' और ''निजी'' व्यापार को अलग-अलग करें और अधिकारियों का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, बिल्क प्रतिभा के आधार पर करें। इसके बाद प्रमुख हान (सत्सुमा, चोशू, तोसा और हिजन) ने अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने की पेशकश की और यह आग्रह किया किः

''राजसभा जैसा आवश्यक समझे आदेश जारी करें, जिससे बड़े राज्यों की भूमियों को बेच डाला जाए और उनमें बदलावों का निर्णय लिया जाए ''' जिससे राज्य के, बड़े और छोटे दोनों तरह के मामले एक ही अधिकारी के हाथों में आ सकें।''

इससे अनुकूल अवसर बना, लेकिन इससे पहले कि सम्राट कोई निर्णय लेते, और भी अधिक बातचीतों और राजनीतिक प्रयासों का दौर चला, तब जाकर कहीं 29 अगस्त 1871 को सम्राट ने एक आदेश जारी कियाः

''हम यह आवश्यक समझते हैं कि देश का शासन एक ही अधिकारी के हाथों में केंद्रित हो, जिससे सुधार सार रूप में ही नहीं यथार्थ रूप में भी लागू हो '''''।''

असंबद्ध शब्दों वाला यह दस्तावेज जिसने एक वर्षों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, अत्यधिक महत्वपूर्ण था। हान की समाप्ति ने समूचे जापान में एक (प्रांतीय) प्रशासकीय व्यवस्था का विस्तार करने और एक केंद्रित सत्ता की स्थापना करने का आधार बनाया, इस बार, इन कदमों की प्रेरणा पश्चिम से मिली, पहले की तरह चीन से नहीं।

### 10.2.2 राष्ट्रीय सेना

राष्ट्र राज्य बनाने की दिशा में दूसरा बड़ा कदम एक राष्ट्रीय सेना की स्थापना थी। परंपरा से, हथियार रखने का विशेषाधिकार केवल सैमुराई के पास था, यह उसी समय से था जब सोलहवीं शताब्दी में हिदेयोशी ने एक अभियान चलाकर किसानों के हथियार रखवा लिए और एक सापेक्ष शांति का दौर कायम किया थाँ। तोकुगावा के अंतिम वर्षों में बकुफु और हान दोनों ने ही अपने सैनिक संगठन में सुधार किया। चोशू में साधारण नागरिकों की एक अनियमित सेना खड़ी की गयी और इसी धारा को आगे बढ़ाते हुए चोशू के ओमुरा मासुजिरों ने जुलाई 1869 में एक अनिवार्य भर्ती वाली सेना का प्रस्तााव रखा। इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, क्योंकि यह वर्षों से चले आ रहे विशेषाधिकारों पर प्रहार था और, इसके अलावा, ओमुरा के प्रस्ताव में यह मांग थी कि रंगरूट अपने राज्यों से सभी तरह के संबंध तोड़ लें।

सैनिक बलों को सुधारने के प्रस्ताव का समर्थन एक प्रमुख मेजी नेता, यामागाता आरितोमो, ने किया। उसने पश्चिमी प्रशिक्षण और संगठन-पद्धतियों के महत्व को देखा और उसने यह भी देखा कि प्रशिक्षित रंगरूट अपने गांवों को लौटेंगे और एक आरक्षित वल बन जाएंगे। उसने लिखा कि अपने देश में स्थिरता और विदेशी हमलों से प्रतिरक्षा ''एक ही समस्या के पहलू थे।''

जनवरी, 10, 1873 को एक अनिवार्य भर्ती कानून लागू किया गया जिसमें बीस वर्ष की अवस्था के वयस्कों के लिए तीन वर्ष सिक्रिय सैनिक सेवा और चार वर्षों की आरक्षित सेवा अनिवार्य कर दी गयी। देश को छह सैनिक जनपदों में बांटा गया जिनमें कुल 31,000 पुरुष थे। अनिवार्य भर्ती कानून ने एक विविध स्वरूप को एकरूपता और केंद्रीकरण प्रदान किया। 1853 से, राजनीतिक सत्ता केंद्रों की अनेकता के कारण अनेक स्वरूपों को आजमाया गया था। लेकिन मेजी के सत्ता में आने के बाद ही यह आवश्यक हुआ कि आंतरिक

अशांति को समाप्त करने और राष्ट्र को विदेशी हमले के खतरे के भय से बचाने के लिए एक कारगर सेना हो। हान अब (प्रशासकीय) प्रांत बन गये थे, वे भी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे और इन समस्याओं के साथ आंतरिक अशांति के भय ने भी उन्हें एक केंद्रीकृत सैनिक ढांचे को स्वीकार करने को उद्धत किया। एक सैनिक मामलों के मंत्रालय (ह्योबूशो) की स्थापना 1869 में की गयी और इसे पूरी तौर पर नौकरशाही ढांचे का अंग बना लिया गया।

आज दृष्टिकोण यह है कि जापान पर 1870-71 की फ्रांस प्रशा जंग में प्रशा की जीत का प्रभाव पड़ा और उसने फ्रांसीसी आदर्श को छोड़कर प्रशायी व्यवस्था को अपनी सेना के गठन के मामले में अपना आदर्श बना लिया। लेकिन, वास्तव में उसने जंग के एक महीने बाद फ्रांसीसी आदर्श को अपना लिया। अनिवार्य भर्ती को संस्था का रूप इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि सैनिक बलों के लिए रंगरूटों की कमी थी, अगर 450,000 बेरोजगार सैमुराई में से आधों को भी भर्ती कर लिया जाता तो, जापान के पास उससे भी अधिक सैनिक होते जितने उसके पास 1880 के दशक में थे।

### 10.2.3 भूमि-कर और पेंशन

केंद्र-केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक तीसरा बड़ा कदम था भूमि कर को संस्था का रूप देना। तोकुगावा काल में, कर चावल के रूप में दिया जाता था और कई स्थानीय प्रथाएं और रीतियां प्रचलन में थीं। इसके अलावा, भूमि को बेचा नहीं जा सकता था। इस जटिल समस्या पर बहस हुई और मार्च 1872 में भूमि बेचने पर लगी पाबंदी को समाप्त कर दिया गया और गहन बहसों के एक दौर के बाद नकदी के रूप में दिए जाने वाले कर को 1873 में स्थापित किया गया। कर का आधार भूमि के पूंजीगत मूल्य का चार प्रतिशत रखा गया। इस उपाय को किस ढंग से लागू किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके विस्तृत विवरण में जाये बिना, यहां यह कहना पर्याप्त होगा कि सरकार के पास अब राजस्व का एक स्थिर स्रोत था।

चौथी बड़ी समस्या थी सैमुराई की पेंशन में संशोधन करना (उन्हें कम करना)। तोकुगावा काल में सैमुराई को, उनके पद के विशेषाधिकार के तौर पर वजीफे दिये गये थे। इन वजीफों पर वित्त मंत्रालय की भूमि कर से होने वाली कुल आमदनी का एक तिहाई खर्च हो जाता था। नयी सरकार इन कीमतों को कम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनमें वर्षों से काफी कटौती होती चली आयी थी और वह व्यापार पर करों के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती थी क्योंकि इसका प्रयास वृद्धि या विकास को बढ़ावा देना था। इसलिये, वह इस विशेषाधिकार को समाप्त करने की भी इच्छुक थी। फिर भी, इस तरह के किसी कदम के राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक था कि इसे संयम और सावधानी के साथ लागू किया जाता। कुछ संभावित प्रस्तावों को आजमाया गया लेकिन अंत में मार्च 1876 में वजीफों के संशोधन (उनमें कमी) को सभी सैमुराई के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सबसे कम वजीफा धारकों को वार्षिक मूल्य की चौदह गुनी कीमत के सरकारी ऋण पत्र (बांड) दे दिये गये। इन ऋण पत्रों पर सात प्रतिशत ब्याज की दर रखी गई। इनसे बड़े वजीफा धारकों को उनके वार्षिक मूल्य की पाँच गुनी कीमत के ऋण पत्र दे दिये गये जिन पर 5 प्रतिशत ब्याज की दर थी।

सैमुराई के वजीफों में कटौती से सरकारी खर्च में 30 प्रतिशत की कमी आ गई और इसका लाभ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महसूस किया गया, लेकिन इसने सामाजिक और राजनीतिक समस्याएँ खड़ी कर दीं। सामाजिक विशेषाधिकारों का नुकसान होने से उनका गुस्सा भड़क उठा और नयी सरकार के विरुद्ध विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला। इनमें सबसे गंभीर था 1877 का सत्सुमा विद्रोह जिसका नेतृत्व सत्सुमा के प्रभावशाली हान के मेजी नेता, साइगो ताकामोरी, ने किया।

ये सुधार जिन महत्वपूर्ण बदलावों को प्रतिबिंबित करते हैं और जिन्हें उन्होंने लागू किया, उन बदलावों ने शासन या राज के आधार और उसकी प्रकृति को बदल दिया। वाइम्यों और उच्च सैमुराई और कुछ दरबारी सामंतों को भी सत्ता से वंचित कर दिया गया, वैसे उनके पास आर्थिक अधिकार फिर भी रहे। निचले स्तरों पर कई सैमुराई किसानों में मिल गये, दूसरे जमींदार या सौदागर हो गये और कुछ नौकरशाही या सैनिक बलों में शामिल हो गये। सत्ता अब केंद्र में केंद्रित हो गयी और उस पर सम्राट की अध्यक्षता वाली राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण हो गया, जिसके अधीन नौकरशाही और सशस्त्र बल थे। इस संदर्भ में एक ऐसी संवैधानिक सरकार बनाने के लिये बदलाव लाये गये जो पश्चिमी ताकतों को अधिक स्वीकार्य हों, क्योंकि सब बातों से ऊपर, जापान अपने ऊपर थोपी गयी असमान संधियों को निरस्त करने को इच्छुक था। इस उद्देश्य के लिये जापान को अपने आपको एक आधुनिक राष्ट्र का रूप देना आवश्यक था जिसका अर्थ उस समय ''पश्चिमीकृत राष्ट्र'' होता था।

जापान :	आधुनिकीकरण	की
ओर संब	मण	

1)	जापान में	राष्ट्रीय	सेना	का गठन	कैसे औ	र क्यों	किया	गया ?	लगभग	10 पंक्तियों	में उत्तर दी	ोजिए।
			*									
		-										
							•••••		**********			
												,

- 2) निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-से सही (√) हैं और कौन से गलत (×) हैं? निशान लगाइये।
  - i) जापान को प्रांतीय (प्रशासनिक) व्यवस्था कायम करने की प्रेरणा चीन से मिली।
  - ii) भूमि की बिक्री पर लगी पाबंदी 1872 में समाप्त की गयी।
  - iii) जापान ने अपनी सेना के लिये प्रशा को आदर्श बनाया।
  - iv) सैमुराई के वजीफों में संशोधन से सरकारी खर्च कम हो गया।

### 10.3 संविधानवाद की ओर

बोध प्रश्न ।

फरवरी 11, 1889 को प्रभावी होकर मई 3, 1947 तक चलने वाला मेजी संविधान वह बुनियादी दस्तावेज था जिसने अंतिम राजनीतिक ढांचे को रूप दिया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को केवल इस दस्तावेज का अध्ययन करके नहीं समझा जा सकता। संविधान को रूप देने का काम उभरते राजनीतिक संगठनों के आवेदनों और प्रदर्शनों और शासक अल्पतंत्र के भीतर चलने वाली बहस और विचार-विमर्श के संदर्भ में हुआ। संविधान को कुछ अन्य निर्णायक राजनीतिक बदलाव लागू किये जाने के बाद ही प्रभावी किया गया। संविधान की प्रकृति और इसे रूप देने के लिये प्रयुक्त प्रक्रिया और विरोधी गुट के विचारों की छानबीन करने से मेजी कालीन जापान की सत्ता की प्रकृति और चित्र का संकेत मिलता है। पहले हम मेजी-संविधान पर गौर करेंगे, फिर विरोधी गुट की मांगों पर, और अंत में मेजी कालीन राजनीतिक ढांचे की मुख्य विशेषताओं पर विचार करेंगे।

### 10.3.1 मेजी का संविधान

जापान में संविधानों का एक लंबा इतिहास रहा है, और सबसे पहला संविधान 17 अनुच्छेदों वाला संविधान है जिसे 604 ई. में शोतोकू ताइशी ने जारी किया। लेकिन आधुनिक ढंग के संविधान का श्रेय चीनी आदर्शों की अपेक्षा पश्चिमी कानूनी प्रभाव को अधिक जाता है। मेजी काल से पहले सामंतों की विचारक सभाएं रही थीं और एक सार्वजनिक प्राधिकरण या कोगी की परंपरा थी जिसे अनेक विद्वान वह आधार मानते हैं जिस पर आधुनिक संविधानवाद का सफल निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में, विचार-विमर्श के जिरए निर्णयों पर पहुंचने की परंपरा थी। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि तोकुगावा काल के दौरान शोगुन के अधिकार सामंती नहीं, बल्कि विशुद्ध तौर पर एकतंत्रीय या स्वेच्छाचारी किस्म के थे।

प्रारंभिक महीनों में मेजी के नेताओं ने एक वक्तव्य जारी किया। यह वक्तव्य असल में एकता के लिये की गयी एक अपील थी जिसने भावी बदलाव की नींव रखी। सम्राट ने 6 अप्रैल, 1868 को जो शपथ-घोषणा पत्र जारी किया उसमें पांच अनुच्छेद थे। इनमें से पहले अनुच्छेदों में यह वचन था—''व्यापक रूप से बुलायी गयी एक सभा की स्थापना की जाएगी और राज्य के सभी मामलों का निर्णय सार्वजनिक विचार-विमर्श से किया जाएगा'' इसने एक संवैधानिक शासन व्यवस्था का आधार तैयार किया।

संविधान की प्रकृति के बारे में निर्णय लेते समय जो महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आयी उनका संबंध इनसे थाः

- किस गति से इन उपायों को लागू किया जाएगा,
- सम्राट की शक्ति और अधिकार, और
- इन कानूनों को पारंपरिक जापानी रीतियों का अंग किस प्रकार बनाया जाएगा कि समाज में विघटन न हो।

**मेजी** नेता समाजवाद के खतरों को भी जानते थे और वे यह नहीं चाहते थे कि जापान को इन समस्याओं का सामना करना पड़े।

मेजी नेताओं में से यामागाता आरितोमो का यह तर्क था कि अगर अत्यधिक तेज गित को अपनाया गया तो इससे जनता कट जाएगी जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। दूसरी ओर, इतो हिरोबूमी का तर्क था कि जापान अब एक प्रस्पर निर्भर विश्व का हिस्सा था और जापान के भीतर सैमुराई को मिले विशेषाधिकार, वजीफे और अधिकार समाप्त किये जा चुके थे, इसलिये, इस बदले वातावरण में जनतांत्रिक विचारों की उपेक्षा करना संभव नहीं था और यह आवश्यक था कि सत्ता में भागीदारी की जाये।

सबसे उदारवादी दृष्टिकोण ओकुमा शिगेनोबू का था जिसने एक अंग्रेजी ढंग की संसदीय व्यवस्था की वकालत की। ओकुमा हिजेन प्रांत से था और एक पार्षद् के रूप में, और 1873-1880 के बीच वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुका था। मार्च 1881 का उसका स्मरण-पत्र एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था जिसमें 1883 तक संसद की स्थापना और 1882 में चुनावों की वकालत की गयी थी। इसमें यह सुझाव भी था कि जिस दल को बहुमत मिले वह सरकार का गठन करे। उसने लिखा, ''संवैधानिक सरकार दलीय सरकार होती है और दलों के बीच होने वाले संघर्ष सिद्धांतों के संघर्ष होते हैं।''

इससे लगभग विपरीत ध्रुव पर स्थित दृष्टिकोण मेजी नेताओं के केंद्रीय गुट के सदस्य और प्रभावशाली सामंत इवाकुरा तोमोमी का था। उसका और इनोवे कोवाशी का तर्क यह था कि इंग्लैंड की तरह जापान में राजनीतिक दलों की कोई परंपरा नहीं थी और वे यहां सफल नहीं होंगे। इसलिये, सम्राट को संसदीय बहुमत से स्वतंत्र मंत्रिमंडल को नियुक्त और भंग करना चाहिये। इस तरह के दृष्टिकोणों का प्रभावशाली अखबारों ने भी समर्थन किया। सरकार का एक करीबी अखबार तोक्यों निची निची शिनबूम सम्राट की दिव्यता का समर्थक था।

राजभक्त परंपरा का यह तर्क रहा था कि जापान की रचना देवताओं ने की थी और सम्राट सूर्य देवी का सीधा वंशज था, जिसका पौत्र जापान का पहला सम्राट हुआ। शाही घराने की वंश परंपरा कहीं भी टूटी नहीं थी और इसने जापान के राजनीतिक ढांचे या कोकुताई को अनूठा बनाया था। कोकुताई का शाब्दिक अर्थ होता है राजनीतिक संकाय या संगठन, और यह शब्द सम्राट के कार्यों के गिर्द चलने वाली बहसों में एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया था। मेजी काल के दौरान इस शब्द की मिथकीय परंपराओं के विरुद्ध तर्क देने के लिए भी, कई प्रकार से विवेचना हुई, लेकिन बाद में यह शब्द एक दैवीय सम्राट के विचार से विशेष रूप से जोड़ दिया गया।

आधुनिकीकरण के एक प्रबल पोषक और प्रभावशाली **मेजी-कालीन** बुद्धिजीवी फुकुजावा ने शाही घराने पर एक लेख लिखा जिसमें उसने यह तर्क दिया कि शाही परिवार को राजनीति से बाहर रहना चाहिए क्योंकि वह सभी का था। सम्राट एकता और निरंतरता का प्रतीक रहेगा, और सत्ता जिम्मेदार दलों के बीच घूमेगी।

इन बहसों से शासक तंत्र के भीतर विचारों की विविधता का और उस स्थित का पता चलता है जिसमें ये नेता राष्ट्रीय नीति के अनिवार्य लक्ष्यों पर व्यापक रूप से सहमत होते हुए भी विभिन्न विचार या दृष्टिकोण रखते थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया इतो हिरोबूमी की अध्यक्षता वाले एक दल ने अत्यंत गोपनीयता में चलायी, जर्मनी के कानूनी विद्वान एच. रेसलर और ए. मोर्स उनके सलाहकार थे। लेकिन, इस प्रारूप के तैयार होने से पहले ही, एक शाही अध्यादेश ने 1884 में एक अभिजातवर्गीय व्यवस्था बना दी और 1885 में एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कायम की जिसमें इतो हिरोबुमी पहले प्रधानमंत्री बने।

अक्तूबर 11, 1881 को एक शाही आदेश में एक संविधान का वचन दिया गया जिससे "हमारे शाही वारिसों को अपने दिशा निर्देश के लिये एक शासन मिल सके।" यह संविधान 1890 में प्रभावी होना था और इसका बुनियादी सिद्धांत यह था कि संसदीय जनतंत्र पर अंकुश रहना चाहिए नहीं तो वह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भंग कर देगा। विरोधी दल समस्याएं खड़ी न कर पायें, इसे और भी सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक सभाओं और प्रकाशनों पर नियंत्रण की गरज से कानून लागू किये गये। अंत में,

1887 में शांति संरक्षण कानून बनाकर पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा दे ''जो अशांति की योजना बनाता है या अशांति भड़काता है, या जिसे सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली कोई भी योजना बनाने का दोषी पाया जाता है।''

संविधान का अंतिम प्रारूप अप्रैल, 1888 को पेश किया गया और 11, फरवरी, 1889 को सम्राट ने यह संविधान अपनी प्रजा को भेंट किया इस दिन को किगेनसेत्सु कहा जाता है, जब पहले सम्राट जिम्मू की कथित वार्षिकी मनायी जाती है।

#### 10.3.2 बहस

इस बात को लेकर बहसें चलती हैं कि संविधान केवल एक दिखावा था या सामाजिक बदलाव लाने का सच्चा प्रयास। एक दृष्टिकोण के अनुसार मेजी अल्पतंत्र हान (सत्सुमा, चोशु आदि) के गुटो (हानबत्सु) का एक गठबंधन था, लेकिन इस दृष्टिकोण में मेजी सरकार के भीतर काम कर रही केंद्रीयकरणकारी शक्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है। दूसरे विद्वानों ने तर्क दिया कि प्रशा की तरह जापान ने भी देरी से विकास होने के कारण सामाजिक राजतंत्र के विचार को चुना और वह आधुनिकीकरण के अपने कार्यक्रम को चलाने में समर्थ रहा। संविधान में एक ओर तो (अनुच्छेद 1) यह प्रावधान था कि ''जापान के साम्राज्य पर अनंत काल से चले आ रहे सम्राटों के वंश का शासन होगा,'' और, दूसरी ओर (अनुच्छेद 4) यह भी प्रावधान था कि ''सम्राट साम्राज्य का अध्यक्ष है, जिसमें प्रभुसत्ता के सारे अधिकार निहित हैं।'' परमपावन अधिकारों वाले एक परंपरागत सम्राट को बनाये रखने का यह दोहरापन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक तनाव का स्रोत बना रहा, फिर अमेरिका की कब्जा करने वाली सेनाओं ने एक नया संविधान थोप दिया।

मेजी राज्य के "निरंकुशतावादी" स्वरूप के प्रस्ताव यह तर्क देते हैं कि सैमुराई अपने आपको एक सामंतवादी व्यवस्था से मुक्त करने के लिए शाही संस्था का इस्तेमाल करने में समर्थ रहे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि कोई भी अकेला वर्ग वर्चस्व की स्थिति में नहीं था। सामंती शक्ति का पतन हो रहा था, किसान विद्रोह कर रहे थे और बुर्जुआ का अभी उदय हो रहा था। ई.एच.नार्मन का तर्क था कि यही निरंकुशतावादी राज्य आधुनिकीकरण के भारी काम को अंजाम दे सकता था। इस तर्क से जुड़ा किसान विद्रोह का यह दृष्टिकोण है कि इन विद्रोहों से भय का ऐसा वातावरण बनेगा कि किसी भी जनक्रांति से सामाजिक व्यवस्था को खतरा हो जाएगा, और इसलिए, निरंकुशतावाद अनेक गुटों को स्वीकार्य था।

			19
13	13		64

7	P15 1 AF					
	अल्पतंत्र के भीतर संविध	गन की प्रकृति को	लेकर वि	भिन्न दृष्टिकोण	ं के विषय में बत	गाइये। लगभग दस
	पंक्तियों में उत्तर दें।					
						× 1001
				*******		
	.,					

- निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-से सही (√) हैं, और कौन-से गलत (×) हैं? निशान लगाइए।
  - i) राजभक्त परंपरा सम्राट को सूर्य देवी का सीधा वंशज मानती थी।
  - ii) फुकागावा युकिची यह नहीं चाहता था कि शाही परिवार राजनीति से बाहर रहे।
  - iii) शपथ घोषणा-पत्र के पहले अनुच्छेद ने एक संवैधानिक सरकार की बुनियाद रखी।
  - iv) संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम खुले आम किया गया।

### 10.4 मेजी राज्य के विरुद्ध विरोध और विद्रोह

हम यह देख चुके हैं कि मेजी अल्पतंत्र ने एक नये राजनीतिक ढांचे की रचना के लिये किस तरह से अनेक सुधार लागू किये। इससे शासक अल्पतंत्र के भीतर ही व्यापक बहस हुई, लेकिन, इसने शासक तंत्र के बाहर भी फूट, विरोध और हो-हल्ले को जन्म दिया। इस भाग में हम इन बातों पर विचार करेंगे कि विरोध के स्वर कहाँ-कहाँ उठे, इन विरोधों की प्रकृति क्या थी और इन विरोधी गुटों ने किस विचारधारा को व्यक्त किया।

भूमि कर को लेकर होने वाले विरोधों पर इकाई 12 में विचार किया जाएगा, लेकिन यहां इतना कहा जा सकता है कि विरोधों के बावजूद उपायों को राजनीतिक सफलता मिली और उन्होंने **तोकुगावा** व्यवस्था में मौजूद मनमानेपन के तत्व को समाप्त कर दिया। सामान्य तौर पर इसका लाभ बड़े भू-स्वामियों या जमींदारों को मिला। अनेक परंपरागत अधिकारों की समाप्ति से जमींदार और काश्तकार के बीच झगड़े मुख्य तौर पर लगान के सवाल पर बढ़े। फिर भी, जिस वर्ग पर इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वे ही विरोध कर पाने में सबसे अशक्त थे जैसे, अपना निर्वाह भर करने वाले किसान।

### 10.4.1 विशेषाधिकारों की समाप्ति के विरुद्ध

अधिक हिंसक प्रतिक्रिया पारंपिरक कुलीनों के विशेषाधिकारों के ढांचे को समाप्त करने को लेकर हुई। 1874 और 1877 के बीच होने वाले शिजोकू विद्रोह नये शासन के लिए गंभीर चुनौतियां थीं। इन विद्रोहों का नेतृत्व उन युवा सैमुराई ने किया था जो तोकुगाबा विरोधी आंदोलन में सिक्रय रहे थे और नयी मेजी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर थे। 1874 के सागा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला एतो शिम्पे राज्य पिरषद् का सदस्य था, शिम्पूरेन विद्रोह में भाग लेने वाला माएबारा इस्से सरकार में था, और अंतिम और सबसे गंभीर विद्रोह, 1877 के सन्सुमा विद्रोह, का नेतृत्व करने वाला साइगोताकामोरी मेजी नेताओं के केंद्रीय गुट का सदस्य था और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका था।

कुलीनों को अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों के छिन जाने का ज्ञान हुआ और वे अपने आपको व्यक्त करने के अवसर की तलाश में थे। वे इस सवाल पर एकजुट हो गये कि जापान को कोरिया पर आक्रमण करना चाहिये या नहीं। कोरिया ने जापान के साथ राजनियक और व्यापारिक संबंध खोलने से इंकार कर दिया था और साइगो को आशा थी कि वह इसका इस्तेमाल एक सैमुराई सेना बनाने में कर सकेगा। इसाइगो ने इससे पहले विकास का एक नमूना प्रस्तावित किया था जिसमें उसने शिंतो को एक राज धर्म के रूप में अपनाने के पक्ष में तर्क दिया था, उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिये विशेष उपाय करने और निर्माण या उत्पादन क्षेत्र द्वारा शिजोकू के वजीफों को समर्थन देने की वकालत की थी।

मेजी नेताओं ने सिद्धांत रूप में कोरिया पर आक्रमण करने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन वे इसके समय को लेकर विरोध में थे क्योंकि उनका मानना यह था कि जापान अभी भी काफी मजबूत नहीं था और इस तरह की जोखिम भरी कार्यवाही से चीनी या रूसी हस्तक्षेप को भी आमंत्रण मिलेगा। 1871-73 में युरोप और अमेरिका का भ्रमण करने वाले इवाकुरा अभियान दल (मिशन) को पश्चिम की सैनिक और आर्थिक मजबूती की खूब जानकारी थी। इन नेताओं का तर्क था कि जापान को अपने आधुनिकीकरण के लिए जिन कीमती संसाधनों की तुरंत आवश्यकता थी वह उन्हें किसी और काम में लगाने का बीड़ा नहीं उठा सकता था। इसमें कट्टरपंथियों को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव हुए (इकाई 10 देखिए)

सत्सुमा ने निर्णायक भूमिका निभायी क्योंकि वहाँ **सैमुराई** की आबादी बहुत अधिक थी, क्योंकि ग्रामीण योद्धाओं या गोशी की भी गिनती वहाँ सैमुराई में की जाती थी। शेष जापान में सैमुराई, पूरे तोकुगावा काल में, महली कस्बों में रहते रहे थे और उनका भूमि से कोई सीधा संबंध नहीं था। इन बदलावों का सीधा प्रभाव गोशी के विशेषाधिकारों और आजीविका पर पड़ा, और उन्होंने सरकार विरोधी विद्रोहों को इच्छुक रंगरूट दिये।

इन विद्रोहों की असफलता अपनी सत्ता कायम करने और समर्थन का एक व्यापक ढांचा बनाने में सरकार की सफलता का प्रमाण है। इसका कारण विद्रोही नेताओं की अपने समर्थकों और हमदर्दों को प्रभावी ढंग से संघटित करने और इस्तेमाल करने में उनकी असफलता भी थी। लेकिन सत्सुमा विद्रोह का संगठन बेहतर था और वह अधिक बड़ा भी था जिसमें 22,000 समर्थक थे। सरकार ने 33,000 की एक सेना भेजी और फिर 30,000 की कुमुक भी भेजी। सरकारी सेनाओं की सफलता का कारण विद्रोहियों का संर्कीण राजनीतिक आधार, उनकी युक्तिगत गलतियां भी थीं और एक अनिवार्य भर्ती पर आधारित सेना की श्रेष्ठता भी।

#### 10.4.2 स्वतंत्रता और जनाधिकार आंदोलन

मेजी सरकार को अपनी नीतियों को लेकर अल्पतंत्र के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा। मेजी पुर्नस्थापना के एक प्रमुख हान-तोसा गुट- के इतागाकी ताइसूके और गोतो शेजीरो का गुट एक ऐसा ही गुट था जिसने जनतांत्रिक सरकार के पक्ष में वकालत की। उन्होंने जनाधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत एक उच्चवर्गीय सरकार विरोधी आंदोलन के तौर पर हुई लेकिन धीरे-धीरे इस आंदोलन ने निम्न वर्गीय जनतांत्रिक आंदोलन का व्यापक रूप ले लिया। जनाधिकारों के समर्थक शुरुआत में सैसुराई और धनी किसान (गोनो) थे, जो मेजी पुर्नस्थापना में सिक्रय रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे इनके समर्थकों में स्कूल-अध्यापक, पुरोहित, लघु सौदागर और छोटे जमींदार भी शामिल हो गये। आंदोलन के बदलते चिरत्र में इसके संगठन में आये बदलाव का प्रतिबिम्ब दिखायी देता है।

जनाधिकार आंदोलन जापानी राजनीति की एक दृष्टि को भी आगे रखता है जो उस दृष्टि से भिन्न थी जिसका समर्थन मेजी नेता करते थे। इसलिए, कई समान विशेषताएं होते हुए भी, और आंदोलन के कुछ नेताओं द्वारा सरकार के साथ समझौता कर लेने पर भी, इस भिन्न आधार से एक स्पष्ट विभाजन का पता चलता है। इस आंदोलन ने राजनीतिक चेतना भी पैदा की और राजनीतिक संघों और राजनीतिक दलों की वृद्धि में भी योगदान दिया। अंतिम बात, मेजी पुर्नस्थापना के एक दशक के भीतर ही इस आंदोलन का विकास विरोध और एकजुटता की स्थानीय परंपराओं के विद्यमान होने की ओर संकेत करता है। पश्चिमी उदारवादी विचारों का तेजी से प्रसार केवल इसलिए संभव नहीं हुआ कि शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था, बल्कि इसलिये भी कि यहां एक ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसके भीतर नये विचारों को मिला लेना संभव था।

सन् 1874-1878 के निर्माणकारी दौर में कुछ राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जैसे 1874 में, देशभक्तों का जनता दल (आइकोकुतो), और महत्वाकांक्षा स्थापना समाज (रिशिशा)। इन गुटों की सदस्यता अधिकांश तौर पर तोसा में थी, जिसका नाम कोची (प्रशासक) प्रांत हो गया था, और इतागाकी ताइसूके, उएकी एमोरी, काताओका केनिजी जैसे इसके नेताओं ने एक जनप्रिय सभा और एक प्रतिनिधि सरकार की मांग की। उनका मानना था कि ये संस्थाएं उन समस्याओं का उपचार कर देंगी जो सत्ता के सकेंद्रण, अनिवार्य (सेना) भर्ती, भारी कर और विदेशी मामलों की कुट्यवस्था के कारण बनी थीं।

रिशिशा के घोषणा-पत्र में यह ऐलान था-

''जापान में रहने वाले हम तीन करोड़ लोगों को समानरूप से कुछ निश्चित अधिकार दिये गये हैं, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता का आनंद लेने और उनकी रक्षा करने, संपत्ति प्राप्त करने और उस पर स्वामित्व करने, और आजीविका पाने और सुख की तलाश करने के अधिकार हैं। प्रकृति ने ये अधिकार सभी व्यक्तियों को दिये हैं, और इसलिये, किसी व्यक्ति की सत्ता के हाथों इन्हें छीना नहीं जा सकता।''

फिर भी, सारे विद्वान इन वक्तव्यों को उनकी प्रकट सार्थकता में स्वीकार करने में एकमत नहीं हैं। राबर्ट स्कालापीनो इस भाषणबाजी को एक हथियार के रूप में देखता है जिसका इस्तेमाल करके भूतपूर्व सैमुराई वर्ग के कुछ सदस्य सत्ता हथियाने की कोशिश में थे, क्योंकि वे सैनिक शक्ति या बौद्धिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर अब और निर्भर नहीं कर सकते थे। इतागाकी ताइसूके के विचार जनता के बारें में उदारवादी तो बिल्कुल नहीं थे और वह सैमुराई, धनी किसानों और सौदागरों को अपना आधार बनाना चाहता था। उसका तर्क था कि राजनीतिक शक्ति धनी वर्ग के पास रहनी चाहिए।

सरकारी दमन के बावजूद 1878 से 1881 तक यह आंदोलन फैला क्योंकि इसे भूमि कर में संशोधन से प्रभावित आम लोगों (हिमिन) के असंतोष ने हवा दी। इस असंतोष के कारण विभिन्न संगठनों का, विशेषतौर पर ग्रामीण स्तर पर, गठन हुआ। इन संगठनों पर महत्वपूर्ण काम करने वाले इरोकावा दाइकीची के आंकलन के अनुसार ऐसे 150 से अधिक संगठनों का गठन हुआ। 1881 में जब फ्रीडम पार्टी या ज्यितों का गठन हुआ तब इसके 149 सदस्य थे, और उसी वर्ष नवम्बर में उसने प्रतिनिधि सरकार की मांग के लिये एक आवेदन अभियान में 135,000 से अधिक लोगों को लामबंद कर लिया था।

अल्पतंत्र शासन में शामिल व्यक्तियों ने 1881 में घोषणा की थी कि वे नौ वर्षों के अंदर राष्ट्रीय सभा का गठन कर देंगे। राष्ट्रीय सभा का आयोजन इससे पहले करने की वकालत करने वाले ओकुमा ने त्याग पत्र दे दिया और अपनी अलग पार्टी संवैधानिक सुधार पार्टी (रिक्केन काइशिंतो) का गठन कर लिया। इस पार्टी ने शहरी मध्यम वर्ग का समर्थन लिया जबकि ज्युतो को धनी किसानों का व्यापक समर्थन प्राप्त था, यद्यपि इसके अधिकांश नेता भूतपूर्व सैमुराई थे।

आंदोलन विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा था और संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले अधिवेशनों का आयोजन हुआ था। उदाहरण के लिए, मार्च 1880 में ''राष्ट्रीय सभा स्थापना संगठन'' का जो चौथा आम अधिवेशन हुआ उसमें 28 (प्रशासकीय) प्रांतों में फैले 96,900 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 114 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह गहन राजनीतिक गतिविधि भारी संख्या में निजी तौर पर लिखे गये संविधान के प्रारूपों में भी प्रतिबिम्बित होती थी। 1879 और 1881 के बीच व्यक्तियों ने निजी तौर पर चालीस से भी अधिक ऐसे प्रारूप लिखकर तैयार किये। यह राजनीतिक गतिविधि यह बताती है कि लोग सामंती प्रतिबंधों से निकल कर एक व्यापकतर चेतना का निर्माण करना चाहते थे। इत्सुकाइची के छोटे-से बाजारी कस्बे में स्थिति ज्ञानार्जन और वाद-विवाद संगठन जैसे ग्रामीण स्तर पर गठित संगठन पश्चिमी उदारवादी कृतियों को पढ़ते थे। समाज को बेहतर बनाने के तरीकों पर बहस करते थे और इन "अनजान कुली-कबाड़ियों" ने नागरिक अधिकार संहिता, वैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय संविधान का प्रारूप तैयार करने पर चर्चा की। एक सदस्य चिंबा ताकुसाबुरों ने संविधान का एक पूरा प्रारूप तैयार किया जिसे एक प्रबुद्ध दस्तावेज के रूप में अत्यधिक मान प्राप्त है।

सरकार अपने दमनकारी तंत्र को इस्तेमाल कर रही थी। 1875 और 1877 में अखबारों पर प्रतिबंध लगाने वाले और जन-सभाओं को सीमित करने संबंधी कानूनों के लागू होने से कई समर्थक चुप पड़ गये। 1875 और 1876 के कानूनों के तहत कोई साठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1880 तक यह संख्या तीन सौ से ऊपर पहुंच चुकी थी। 1880 के सार्वजनिक सभा अध्यादेश से पुलिस को राजनीतिक गुटों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के अधिकार मिल गये। इसके अलावा, सैनिकों, अध्यापकों और छात्रों के राजनीतिक सभाओं में भाग लेने पर पाबंदी थी। 1881 में 131 सार्वजनिक सभाओं को भंग किया गया, और 1882 में 282 को। अखबारों के साथ भी इसी कठोरता के साथ सलूक किया गया। टोक्यों स्थित एक अखबार, आजुमा, के संपादक को यह कहने के अपराध में दो वर्ष की जेल और 200 येन का जुर्माना हो गया कि ''और सरकारी अधिकारियों की तरह सम्राट भी एक जन सेवक था।''

सन् 1881 के बाद जनाधिकार आंदोलन में फूट पड़ने लगी और कुछ विद्वानों के अनुसार 1882-1885 के बीच होने वाली हिंसक घटनाएं एक अलग दौर बनाती हैं जिन्हें वे ''उग्रवाद की घटनाएं'' (गेक्का जिकेन) कहते हैं। फुकुशिमा, गुम्मा, कानागावा, इबाराकी और साहतामा में होने वाली इन घटनाओं का आयोजन अधिकांश तौर पर ज्युतों के नेताओं ने ''स्वतंत्रता की सार्वजनिक शत्रु, दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये'' किया था। 1884 में कबासान की घटना में उन्होंने ''नागरिकों के सुख और प्राकृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने'' के लिए सरकार के मंत्रियों की हत्या करने की कोशिश की। कबासान की घटना आर्थिक कठिनाइयों से प्रेरित जनता का विद्रोह नहीं था, बल्कि राजद्रोह द्वारा सरकार बदलने का प्रयास था। लेकिन, 1884 के चिचिबू विद्रोह में जनता की आर्थिक तंगी प्रमुख कारक थी।

चिचिबू विद्रोह को दबाने के साथ इस आंदोलन का अंत हो गया। असल में, एक लंबे अरसे तक आंदोलन होने के बावजूद इस आंदोलन की उपलब्धि न के बराबर रही। मेजी अल्पतंत्र ने 1889 में एक संविधान लागू किया जिसमें राजनीतिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया और 1918 में जाकर ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद से हुई। इस आंदोलन को सीमित करने के कारण थे आंतरिक गुटबाजी, कमजोर नेतृत्व और इसका शाही संस्था की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करना।

फिर भी, आंशिक रूप में आंदोलन को यह श्रेय तो जाता ही है कि उसने **मेजी** नेताओं को इस बात के लिये बाध्य किया कि वे सभा का संयोजन करें और एक संविधान लागू करें, और इसने राजनीतिक दलों की एक व्यवस्था के लिये आधार बनाने में मदद दी। राजनीतिक फूट की ये परंपराएं बाद में समाजवादी और ईसाई आंदोलनों ने जारी रखीं, वैसे जनाधिकार आंदोलन के नेताओं को सत्तादादी शासन की **मेजी** की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावहीन करने में सफलता नहीं मिली थी।

# 10.5 मेजी की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति

उपर्युक्त भागों में हम देख चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का विकास किस तरह हुआ और इसकी बुनियादी विशेषताएं क्या थीं। हमने विरोधी गुटों और उनकी एक भिन्न और अधिक जनतांत्रिक ढांचे की मांगों की भी छानबीन की है। इस भाग में हम राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि में काम करने वाले उन दिशा - निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिन्होंने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। राजनीतिक क्षेत्र में

मेजी अल्पतंत्र के प्रमुख विकास को इस नारे में सटीक बांधा गया है: ''धनी देश, मजबूत सेना'' (फ्यूकोकू क्योंहे)। यह नारा मेजी अल्पतंत्र के इस विचार को अभिव्यक्ति देता है कि पश्चिम के साम्राज्यवादी खतरे के चलते जापान को अपने अस्तित्व और अपनी राष्ट्रीय अखंडता को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक था कि वह एक धनी और समृद्ध राष्ट्र की रचना करे और इसकी रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा सेना खड़ी करे। मेजी नेताओं के प्रयास उन्हीं लक्ष्यों द्वारा निर्देशित थे और उन्हें प्राप्त करने के लिये इन आधारों पर सत्ता के केंद्रीकरण और फूट के दमन की प्रक्रिया चलायी कि इनसे राष्ट्रीय ऊर्जा की हानि होती थी, सामाजिक अव्यवस्था फैलती थी और विदेशी प्रभुत्व का खतरा बढ़ता था।

#### 10.5.1 सम्राट

राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विभूति सम्राट था, जो व्यक्तिगत सत्ता का उपयोग न करने के बावजूद सत्ता का स्रोत बन गया। यही कारण है कि कई जापानी इतिहासकार एक सम्राट व्यवस्था की बात करते हैं या मेजी काल को ''सम्राट व्यवस्था तानाशाही'' (तेन्नासेई जेत्त्ताइशुगी) बताते हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि जापानी में सम्राट के लिये जो शब्द तेन्नो प्रयुक्त होता है उसमें अंग्रजी के शब्द-एम्परर-की तुलना में धार्मिक महत्व का कहीं अधिक बोध है। सम्राट पूरे तोकुगावा काल में सापेक्ष गुमनामी में रहा था। वह वित्त के लिये बकुफु पर आश्रित था। फिर भी, जापानी संस्कृति में उसे केंद्रीय विभूति और सद्गुण का स्रोत माना जाता था। मेजी नेताओं ने दैवीय सम्राट की छिव बनाने और उसे ''राष्ट्र की धुरी'' (इतो हिरोबूमी) के रूप में पेश करने का काम किया।

सम्राट ने 1878-1885 के दौरान देश के छह बड़े चक्कर लगाये इनोवे काओरु के शब्दों में, इन शाही प्रयासों को इस तरह तैयार किया गया था कि इनसे ''न केवल जनता को सम्राट के महान सद्गुण की जानकारी मिले बल्कि सशरीर शाही राज के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का अवसर मिले, जिससे शाही सरकार के विषय में भ्रांतियां दूर होती हैं।''(1878 में इनोवे काओरु)

मेजी नेता बहुत सचेत होकर सम्राट का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिये कर रहे थे, जबिक साथ ही शासन में सम्राट की भागीदारी को भी बहुत कम कर दिया गया और वह उस जमाने के अभिव्यक्तिपूर्ण जुमले में ''बादलों से ऊपर'' रहता था। सम्राट को एक अलग और दूरस्थ शासक के रूप में पेश किया गया जो राजनीति से ऊपर था। मोरी आरीनोरी के शब्दों में वह ''बेजोड़ पूंजी, निष्ठा और देशभिक्त बनाने के उद्यम में सबसे बड़ा संभावी खजाना बन गया।''

गोतो यासुशि सम्राट व्यवस्था के विकास को तीन कालों में बांटता है-

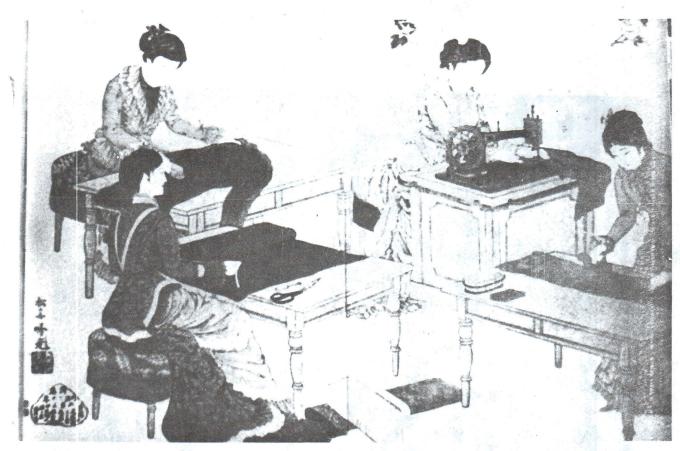
- पहला, 1868 से 1884, जिसमें व्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं का निर्माण हुआ,
- दूसरा, 1885 से 1895, जिसमें व्यवस्था को लागू किया गया, और
- तीसरा, 1895 से 1905, जिसमें पुर्नसंरचना का काम हुआ।

यह व्यवस्था नौकरशाही और सेना के दो स्तंभों पर टिकी थी।

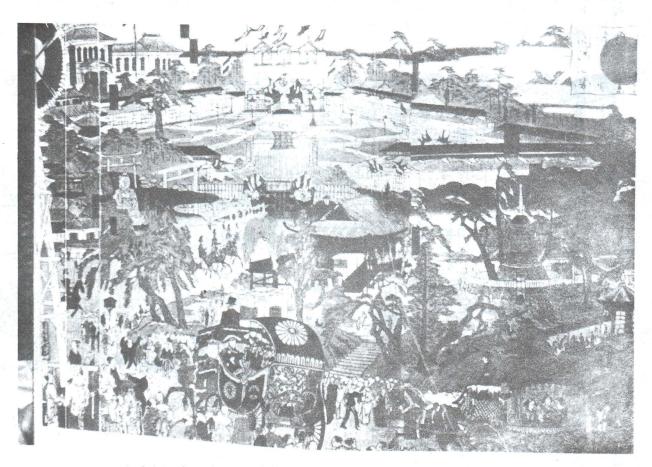
### 10.5.2 नौकरशाही

नौकरशाही ढांचे को बनाने में समय लगा, लेकिन 1872 तक नौकरशाहों की 15 श्रेणियों वाली एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था बन चुकी थी। इनको तीन बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता था, जिनमें से पहली दो श्रेणियों के नौकरशाहों की नियुक्ति सीधे सम्राट के द्वारा होती थी और उनके साथ कानून के हाथों भी अलग व्यवहार होता था। इसके अलावा, भर्ती की नीति ऐसी थी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग पहुंच कर सकते थे और बहुत कम प्रतिशत सामंत और सैमुराई नौकरशाही में शामिल होते थे। इन अधिकारियों के अधिकार और विशेषाधिकार उनके जन्म के आधार पर नहीं थे, बल्कि इसलिए थे कि वे सम्राट के कर्मचारी थे, इसी तरह, सेना सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी और बाद में उसने इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडलों को गिराने और अपने विचार लागू करने में किया। (विस्तृत विवरण के लिये देखिये इकाई 23)।

मेजी सरकार ने राजनीतिक संस्थाएं तो बनायीं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि को वैधानिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया। वह राजनीति को एक ऐसी वस्तु मानती थी जिससे लोगों में फूट पड़ती थी और जो स्वार्थी गुट हितों की प्रतीक थीं। वह सम्राट को निष्पक्ष ढंग से राष्ट्र की इच्छा और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभूति के रूप में पेश करती थीं। इसे लागू करने के लिये गुटों को राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी से बाहर रखा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नाबालिगों, स्त्रियों, अध्यापकों और सैनिकों के राजनीतिक सभाओं में जाने पर पाबंदी थी। सैनिकों और नौसैनिकों को जो राजाज्ञा मिलती थीं, उसमें यह



1. मेजी काल के दौरान वेशभूषा की पाश्चात्य शैली जापान के आधुनिकीकरण में एक उद्योग बन गया



2. यह चित्र केन्द्रीय सत्ता के सुश्पर के पञ्चात् आर्थिक क्षेत्र में जापान के अत्यधिक विकास को परिलक्षित करता है; राजा एवं रानी का आरामन जापानियों में गर्व की अनुभूति का प्रेरक है

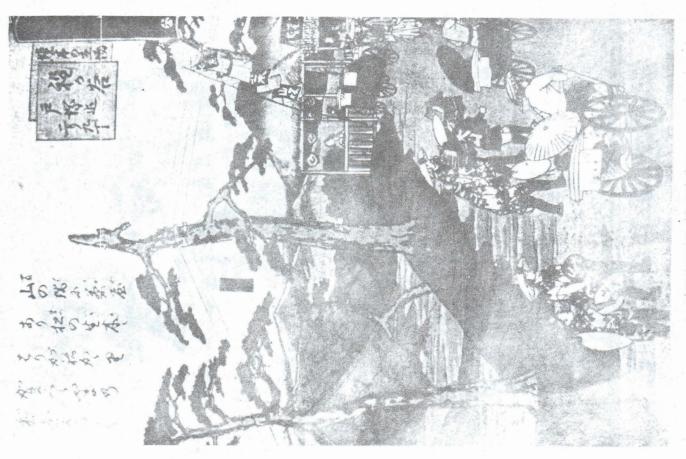




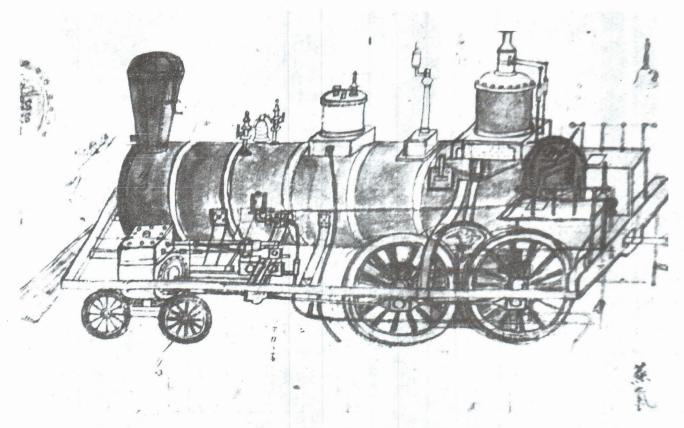
रेशम बुनाई फैक्ट्री, भवन निर्माण पाञ्चात्य औद्योगिक वास्तुकला को दर्शाता है







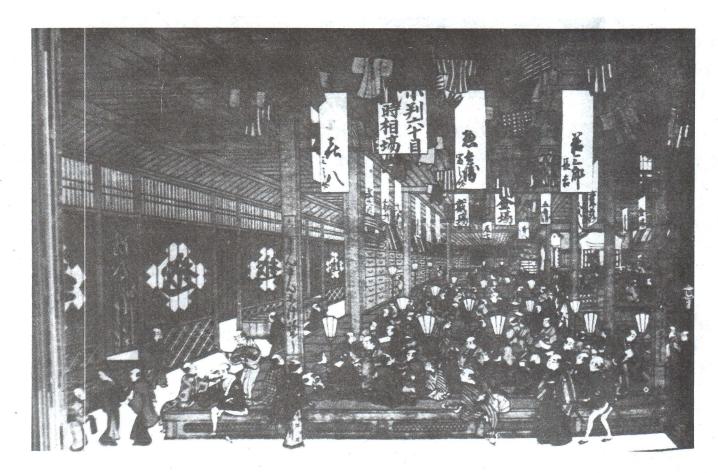
रानागाफ मचार व्यवस्था होते पदान म गई हर ता

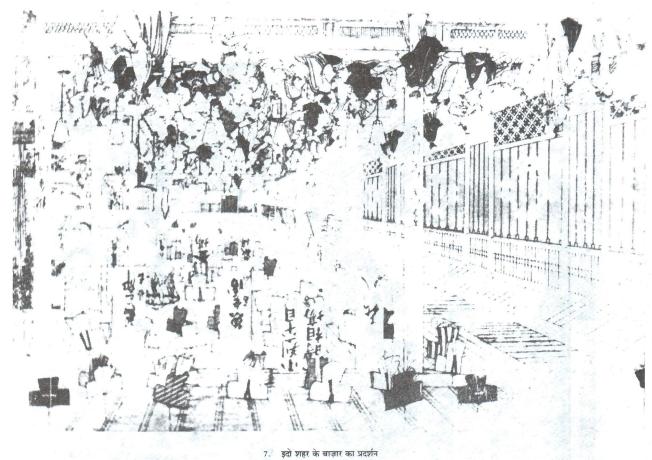


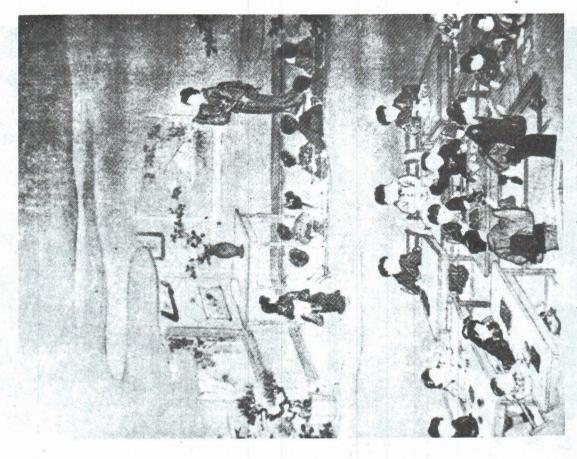
6. भाप के इंजन का प्रयोग विकास के क्षेत्र में एक प्रभावशाली कदम था



8. किसान दैम्यों को कर देते हुए









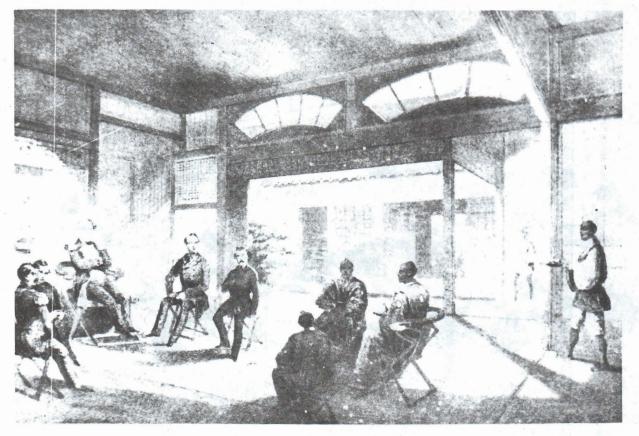
9. बच्चों की शिक्षा की पाष्रचात्य शैली पर आधारित किंडरगार्टन स्कूल

10. मेजी राजा (1852-1912)

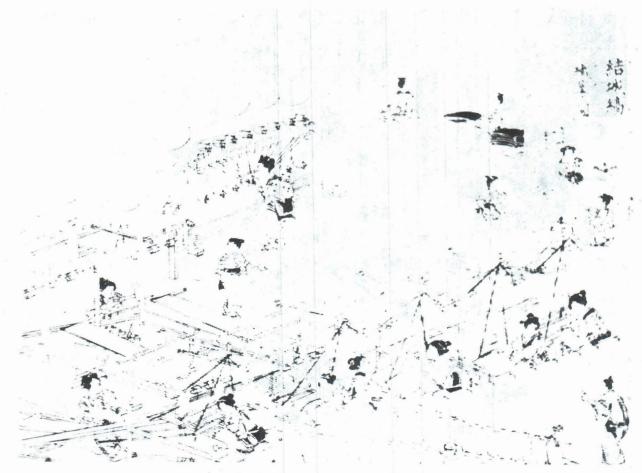


पूर्व मेजी काल का एक किंडरगार्टन

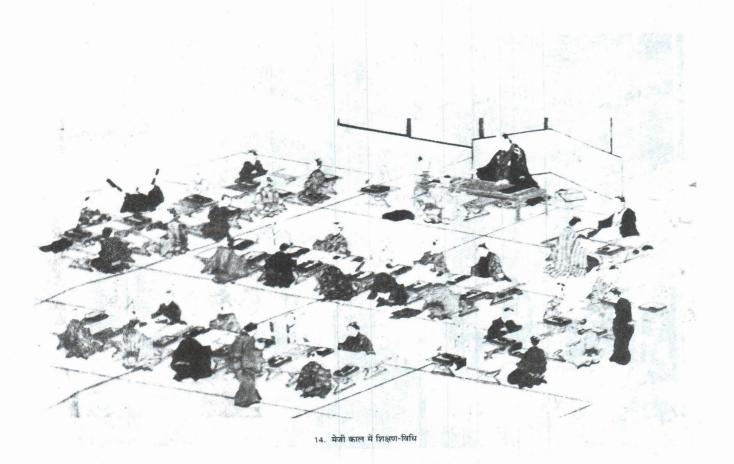




12. जापान और अमेरिका के मध्य एमीटी की संधि पर हम्ताक्षर करते हुए कोमोडोर पेरी और जापानी अधिकारीगण



13. महिलाओं द्वारा रेशम की बुनाई एवं कताई समाज में श्रम-विभाजन को इंगित करती है



जापान में आधुनिकीकरण-।

लिखा रहता था— ''न तो वर्तमान राजनीति से पथभ्रष्ट होओ और न राजनीति में दखल दो, बल्कि पूरे मन से अपनी निष्ठा (या, राजभिक्त) के बुनियादी कर्त्तव्यों का पालन करो।'' स्त्रियों को 1922 तक राजनीतिक कार्यों से घर से बाहर जाने की अनुमित नहीं थी।

मेजी सम्राट ने 1912 में अपनी मृत्यु तक राज्य किया और उसके राज की विशेषता यह रही कि उस दौर में जापान ने एक बंद और पृथक देश से एक बड़ी विश्व शिक्त की ओर संक्रमण किया। जापानी संस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव आये और, हिचक के साथ ही सही, एक संवैधानिक ढांचे का निर्माण हुआ। दाएत (जापानी संसद) शासक अल्पतंत्र पर कुछ अंश तक अधिकार और प्रभाव जमाने में समर्थ रही। इन संभावी और संकोचपूर्ण उपायों से एक दलीय व्यवस्था का विकास हुआ और राजनीतिक बहस बढ़ी, लेकिन शुरुआत से ही मेजी नेता राष्ट्रीय नीति के संबंध में पहल करने और निर्णय लेने में समर्थ रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने नौकरशाही और सेना दोनों पर ही नियंत्रण रखा और उन दोनों को ही संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर रखा। महत्वपूर्ण संस्थाएं और मंत्रालय सीधे सम्राट के अधीन काम करते थे। यही कारण है कि बाद के दौरों में बदलाव होने के बावजूद कोई हिंसक सामाजिक उथल-पुथल नहीं हुई क्योंकि विभिन्न सरकारी संस्थाएं सत्ता के लिये तिकड़म में लगी हुई थीं। इस तरह, 1930 के दशक में सेना ही सरकार के भीतर प्रमुख शिक्त के रूप में उभरी।

ोध प्रश्न 3					
) जापान में ज	नाधिकार आंदोल	न के विषय में ल	गभग 15 पंक्तिय	मों में लिखिए।	
*****			***************************************		
		·····			
	·······································				
			10 7	Y	
*******					
			·		
				H 4:	
राजनीतिकः व	यवस्था में सम्राट	की स्थिति के वि	षय में लगभग	10 पंक्तियां लिखिए	1
					Section 1972
3300 00 3					
					n

- 3) रिक्त स्थानों को भरिए:
  - i) रिशिशा एक ...... संगठन था जो ..... के लिये अधिकारों की ..... करता था।
  - ii) इवाकुरा मिशन "" पर आक्रमण के "" था।
  - iii) गोशी ..... योद्धा थे जिन्हें ..... भी माना जाता था।
  - iv) इत्सुकाइची स्थित संगठन में '''' का एक '''' व्यवस्था का और एक '''' अधिकार संहिता का प्रतिरूप तैयार करने पर चर्चा होती थी।
  - v) नौकरशाही में भर्ती की शाही नीति ऐसी थी कि ..... सामाजिक वर्गों के लोग ...... कर सकते थे।

### 10.6 सारांश

मेजी काल में बदलाव लाने का काम नेताओं के एक छोटे गुट ने किया जिसने मेजी पुर्नस्थापना लाने में मदद की थी। वे आंशिक तौर पर जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में बदलने की इच्छा से प्रेरित थे, जिससे वे असमान संधियों में संशोधन कर सकें। वे एक शक्तिशाली और समृद्ध देश के निर्माण में भी रुचि रखते थे। उन्होंने शाही संस्था जैसी विद्यमान संस्थाओं या धार्मिक विचारों का उपयोग धीमा और क्रमिक बदलाव लाने के लिये किया। मेजी नेता सामाजिक विघटन और पश्चिमी राष्ट्रों से विघटनकारी विचारों के प्रवाह की संभावना को लेकर चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने प्रशा जैसे चुनिंदा देशों से आदर्श लेकर जापान के अनुकूल राजनीतिक ढांचा तैयार करने का काम किया।

विरोधी गुटों के (विपक्षी) आंदोलनों की आकांक्षा भी जापान का निर्माण करने की थी, लेकिन उनकी दृष्टि मेजी अल्पतंत्र की दृष्टि से भिन्न थी। परंपरागत कुलीनों शिजोकू के मेजी-विरोधी आंदोलन प्रगतिशील नहीं थे और वे विशेषाधिकारों के हनन और परंपरागत अधिकारों की समाप्ति से उठे थे। ये कुलीन बाजारी शिक्तयों के आगे फेंक दिये गये जिन्हें न वे समझ पाये और न नियंत्रित ही कर पाये।

मेजी के विरोधों में, जनाधिकार आंदोलन अपने पहले दौर में एक उदारवादी और जनतांत्रिक विरोध का प्रतीक रहा, लेकिन धीर-धीरे दूसरे प्रभावित सामाजिक गुटों के इसमें शामिल होने के साथ इसमें राज्य की सत्ता के लिये खतरा पैदा करने वाले गुट भी शामिल हो गये। इस आंदोलन की असफलता के लिये अनेक कारक उत्तरदायी थे, जैसे—गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व, लेकिन बुनियादी तौर पर मेजी सरकार वैचारिक और संस्थागत दोनों धरातलों पर इतनी जमी हुई थी कि उसे उखड़ना संभव नहीं था।

जो राजनीति बनी उसके बुनियादी ढांचे में दोहरापन था, जो आने वाले वर्षों में समस्याओं का कारण बना। जापान एक केंद्र केंद्रित और आक्रामक राष्ट्र बन गया और उसने शाही दिव्यता का इस्तेमान न केवल अपनी जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिये, बल्कि अपनी सीमाओं के विस्तार के लिये भी किया। आतंरिक दमन और बाहरी आक्रमण उसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उभरे। जनाधिकार आंदोलन जनता की आकांक्षा पर आधारित एक जनतांत्रिक सरकार के जिस विचार को लेकर चला था वह तो निस्काम या व्यर्थ हो गया, लेकिन वह दूसरी पीढ़ियों के जनवादियों को प्रेरणा देता रहा।

## 10.7 शब्दावली

**कोगीः** सार्वैजनिक विचार-विमर्श। इस शब्द का प्रयोग तोकुगावा काल के शोगुन के संदर्भ में भी होता था। उस दौरान ''शोगुन'' शब्द का प्रयोग बहुत कम होता था।

**गोशीः** योद्धा, जो सत्सुमा में गांवों में रहते थे। सैमुराई को तो महली कसबों में रहना होता था, लेकिन इन योद्धाओं को सैमुराई की बराबरी पर रखा जाता था।

शिजोक्: पुर्नस्थापना के बाद स्थिति (हैसियत) के अंतर समाप्त कर दिये गये और भूतपूर्व सैमुराई शिज़ोक् के नाम से जाने गये।

# 10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

#### बोध प्रश्न 1

- 1) अपना उत्तर उपभाग 10.2.2 के आधार पर लिखें।
- 2) i)  $\times$  ii)  $\sqrt{\text{iii}} \times \text{iv} \sqrt{\sqrt{\text{iii}}}$

#### बोध प्रश्न 2

- 1) अपने उत्तर में उपभाग 10.3.1 और 10.3.2 में उल्लेखित विभिन्न विचारों को शामिल करें।
- 2) i)  $\sqrt{\phantom{a}}$  ii)  $\times$  iii)  $\sqrt{\phantom{a}}$  iv)  $\times$

#### बोध प्रश्न 3

- 1) अपने उत्तर में विभिन्न राजनीतिक संगठनों, उनके नेताओं, मांगों, और तरीकों का उल्लेख करें। देखें उपभाग 10.4.2.
- 2) सम्राट की स्थिति (हैसियत) का उल्लेख करें और यह भी लिखें कि यह हैसियत सम्राट को क्यों और कैसे दी गयी। अपना उत्तर उपभाग 10.5.1 के आधार पर लिखें।
- 3) i) राजनीतिक, जनता, वकालत
  - ii) कोरिया, विरुद्ध
  - iii) ग्रामीण, सैमुराई
  - iv) संविधान, वैधानिक, नागरिक
  - v) विभिन्न, पहुंच